पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 23, अंक 1/2022

भूजलः अदृश्य को दृश्यमान बनाना

विश्व जल दिवस पर 'कट्स' की वेबिनार

विश्व जल दिवस पर 'कट्स' द्वारा इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के कार्यकारी निदेशक बिपुल चटर्जी ने बताया कि विश्व में वर्ष 1993 से प्रति वर्ष 22 मार्च को 'विश्व जल दिवस' मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, 2022 का विषय 'भूजलः अदृश्य को दृश्यमान बनाना' है। दृष्टि से ओझल हमारे पैरों के नीचे भूजल एवं छिपा हुआ खजाना है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। हमारे पीने का पानी और स्वच्छता, हमारी खाद्य आपूर्ति और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करता है।

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ व सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पीने के सुरक्षित पानी को एक मौलिक अधिकार और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक अपने सतत् विकास लक्ष्यों में सुरक्षित और सस्ते पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्धारित किया है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल, विषय विशेषज्ञ एवं वाटर ऑन एलीमेंट ऑफ लाइफ के लेखक ने वेबिनार में बताया कि पानी को इकोनोमिक कॉमोडिटी माना जाना चाहिए। अभी तक पानी

को आर्थिक वस्तु नहीं समझा गया है, पानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को पानी उपलब्ध कराएं, समान रूप से सभी को गुणवत्ता वाला पानी मिले। भूमिगत पानी का संविधान के अनुसार मालिकाना हक पब्लिक का माना गया है। पानी का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

वेबिनार में अन्य वक्ता के रूप में मैथ्यू चेरियन, अध्यक्ष, केयर इंडिया ने बताया कि राजस्थान में जो परम्परागत रूप से पानी के संरक्षण के लिए कार्य किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। राजस्थान के भौगोलिक वातावरण के अनुसार कई पेड़ पौधे जिनमें खेजड़ी का भूमिगत जल संरक्षण में विशेष योगदान है। इसी तरह से नाड़ी एवं खडीन के माध्यम पानी का संरक्षण किया जाता है और सिंचाई की जाती है। पानी के संरक्षण का जो सामुदायिक ज्ञान इस क्षेत्र के लोगों में है, उसको प्रसारित करने की आवश्यकता है। इस तरह से सतत् विकास 2030 के लक्ष्य -6 स्वच्छ जल तक पहुंचा जा सकता है।

शुभा रामचन्द्रन, हैड वाटर टीम बायो एनवायरमेंटल ट्रस्ट, बैंगलोर ने वेबिनार मे बताया कि शहर में पीने के पानी की समस्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। शहर के लोग भूमिगत पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पानी का स्तर बहुत अधिक नीचे जा रहा है। आम लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि किस तरह से पानी को रिचार्ज किया जाए। भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है।

जॉयदीप गुप्ता, साउथ ऐशिया डायरेक्टर दि थर्ड पोल ने बताया कि भूमिगत पानी की बहुत कमी है, सिंचाई में सबसे ज्यादा भूमिगत पानी का उपयोग पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे अधिक किया जाता है। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी महिलाओं का बहुत अधिक समय पानी के संग्रहण में व्यतीत होता है। पानी के सुरक्षित एवं परम्परागत संग्रहण के ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए सतत् विकास मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। भूमिगत पानी ग्राम की सम्पत्ति है, इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही सिंचाई में पानी के उचित उपयोग के लिए स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वेबिनार के समापन पर सभी वक्ताओं का धन्यवाद करते हुए 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने कहा कि भूमिगत पानी के संग्रहण की आज के समय में बहुत ही अधिक आवश्यकता है। साथ ही, जो पुराने एवं परम्परागत जल संग्रह के संसाधन है, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। भूमिगत पानी के उचित संग्रहण एवं दोहन को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की आवश्यकता है। 'कट्स' सरकार के साथ नेशनल वाटर फ्रेमवर्क पर कार्य कर सकती है। वेबिनार में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अंक में...

- डॉक्टरों से गांवों के सरकारी अस्पताल खाली ... 3
- शहर में गंदगी यथावत, निगम का खजाना साफ 4
- सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगाई ऊंची छलांग 8
- जल जीवन मिशनः प्रदेश में हुआ बेहतर काम 9
- ट्रैफिक नियमों की भ्रांतियां दूर करें 11

बालश्रम उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ

बाल श्रम से मुक्त बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें - बेनीवाल

प्रतापगढ़ जिले में बाल श्रम उन्मूलन परियोजना (प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा) का शुभारंभ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री संगीता बेनीवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड विजन, 'कट्स' इंटरनेशनल व वाग्धारा संस्था द्वारा जिले में मिलकर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी व बेहतर शिक्षा प्रदान करें और अभिभावकों को भी समझाकर और जागरूक कर उन्हें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में तभी सफलता पा सकते हैं, जब सभी मिलकर बाल श्रम के खिलाफ आगे आकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संस्थाओं को आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी बाल श्रम से जुड़े बच्चों का चयन कर उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करें। चाईल्ड हेल्प लाइन भी बाल श्रम में लगे बच्चों को रेस्क्यू कर रही है। अगर 10 बच्चों को भी रेस्क्यू किया तो उन्हें बेहतर शिक्षा और पुर्ननिवास देकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने कहा कि संस्थाओं द्वारा जिले में जो कार्य प्रारंभ किया है वह लोगों को निश्चित रूप से जागरूक करेगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ल्ड विजन इडिंया, 'कट्स' इंटर नेशनल और वाग्धारा संस्था के सयुंक्त तत्वावधान में एक अक्टूबर 2021 से एक दिसम्बर 2024 तक जिले की सुहागपुरा व बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के दो-दो गांवों का चयन कर बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन, पश्चिम क्षेत्र डब्ल्यूवीआई के सहयोगी निदेशक सस्मिता जेना, पश्चिम क्षेत्र डब्ल्यूवीआई के सहायक निदेशक गोहर महमूद ने संस्था के किए जा रहे कार्य एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, सुशासन, मानव विकास, महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार मुद्दों पर कार्य करने की जानकारी दी। वाग्धारा संस्था ने भी इस अवसर पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

'कट्स' ने महिला सुरक्षा व संरक्षण पर किया महिला आयोग की अध्यक्ष को चार्टर प्रस्तुत

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' इंटरनेशनल और निमिषा शर्मा कार्यक्रम अधिकारी 'कट्स' इंटरनेशनल ने रेहाना रियाज़ चिश्ती, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग को महिला सुरक्षा एवं संरक्षण पर काम करने के लिए प्रमुख मुद्दों पर चार्टर प्रस्तुत किया। यह चार्टर मुख्य रूप से समयबद्ध तरीके से आयोग के स्तर पर लंबित सभी शिकायतों और मामलों का त्वरित समाधान, महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर प्रभावी हस्तक्षेप करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर स्थानीय स्वसरकारी निकायों सीएमओ को शामिल करते हुए सतर्कता समितियों के गठन पर केंद्रित है।

इसमें कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप, घरेलू हिंसा, महिला तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के मामलों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए गए हैं। साथ ही राज्य में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन करने तथा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों से राजस्थान के शहरों में सुविधाजनक और स्वच्छ महिला शौचालयों के निर्माण के लिए विशिष्ट बजट आवंटित करने की अपील की गई है। चार्टर में राजस्थान में जेंडर बजटिंग, निर्भया और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने का सुझाव भी दिया गया है। अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर 'कट्स' के कार्यों की सराहना की है और चार्टर में उल्लेखित मुद्दों को लागू करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के प्रति सकारात्मक सहमति दी है।

सही योजना उचित कदम! सुशासन का यह है धर्म !!

डॉक्टरों से गांवों के सरकारी अस्पताल खाली

सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए चिकित्सा विभाग ने अधिशेष स्वास्थ्यकर्मियों को अपने मूल स्थान पर भेजकर व्यवस्था सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन समस्या की जड़ का समाधान अभी भी नहीं मिल पाया है।

प्रदेश के करीब 3 हजार छोटे-बड़े अस्पतालों में से 2500 छोटे जिलों या सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, जहां करीब 75 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी जाने के लिए अनिच्छुक हैं। जबकि उपलब्ध करीब एक लाख नियमित स्वास्थ्यकर्मियों जितने ही कार्मिक गांवों के लिए भी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज, लैब तकनीशियन सहित अन्य आवश्यक संवर्गों के हजारों पद रिक्त होने के बावजूद वित्त विभाग की अनुमति को लेकर रोक-टोक जारी है। *(रा.प., 10.03.22)*

फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम अर्जित करने में राजस्थान में टॉप रहे हनुमानगढ़ जिले में अब बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसीबी की जांच में दो पटवार मंडलों ढंढेला और मलसीसर में ही 8.8 करोड़ रुपए का फर्जी क्लेम उठाना सामने आया है। यहां 1593 बीमा पॉलिसी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।

हैरानी की बात है कि कई ऐसे लोगों ने बीमा क्लेम उठा लिया जिनके पास जमीन ही नहीं है। कई ने तो सरकारी भूमि के खाता या खसरा नंबर का प्रयोग कर फसल खराबा दिखाया और उन्हें क्लेम मिल गया। यही नहीं एक ही फसल का दो-तीन जगह से क्लेम उठाने का मामला भी सामने आया है। अब एसीबी नोहर और भादरा तहसील क्षेत्र की जांच भी करेगी। ऐसा फर्जीवाड़ा अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। मामले की पूरी जांच की जाने चाहिए।

(दै.भा., 05.01.22)

शौचालय की राशि खातों से पार

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता पर साइबर जालसाजों ने डाका डाला है। जालसाजों ने प्रदेश के कई जिलों में ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) की एसएसओ आइडी हैक कर कई लाभार्थियों के लिए आवंटित राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर ली। अभी प्रदेश के 5 जिलों से इसकी शिकायत मिली है।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण पर एक परिवार को 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। एक साथ संगठित रूप से हुई इस ठगी से स्पष्ट है कि योजना के आनलाइन सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी को लेकर खामियां हैं। लगातार रुपए निकलते रहे और भनक तक नहीं लगी। *(रा.प., 27.02.22)*

लाखों गरीबों को नहीं मिल रहा राशन

प्रदेश में 23.75 लाख गरीब लोग 2 रुपए किलो के गेहूं से वंचित हो गए हैं। इसका कारण है कि दो साल बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के सदस्यों के नाम जन आधार में नहीं जोड़े गए। सरकार की बहुउद्देशीय जन आधार योजना को लागू करने के बाद से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों को जनआधार से जोड़ा जा रहा है।

सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड के स्थान पर मान्यता दी गई है। जनआधार से जुड़े सदस्यों के आधार पर 1 जनवरी 2022 से राशन दिया जाना शुरू हो गया। लेकिन इस माह में लाखों गरीब लोगों को गेहूं नहीं मिलने से उनके सामने खाने का संकट बन गया। *(दै.भा., 08.01.22)*

जल जीवन मिशन में घपले पर लगी मुहर

जल जीवन मिशन के प्रचार प्रसार में कथित घोटाले से घिरे जलदाय विभाग के अधिकारियों ने गलत तरीके से 26.89 करोड़ रुपए के भुगतान करने का आदेश दे दिया। चहेती फर्मों को बजट से अधिक कार्यादेश देने के बाद अधिकारियों ने अवैध तरीके से बजट का पुनःनिर्धारण भी कर दिया।

इसके लिए अफसरों ने जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के नियमों को भी दरकिनार कर दिया। जबकि विभाग के ही एक अधिकारी ने बजट के पुनःनिर्धारण करने से मना कर दिया था। नियमानुसार बजट के पुनः निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्शन कमेटी अधिकृत होती है। कमेटी में भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। कमेटी की बैठक हुए बिना ही चहेती फर्मों को भुगतान के आदेश कर दिए। *(रा.प., 24.03.22)*

रोजगार पैदा करने में राजस्थान फिसड्डी

बेरोजगारी में राजस्थान, हरियाणा, झारखंड शीर्ष पर है। वहीं ओडिशा में सबसे कम एक फीसदी बेरोजगारी दर है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से सभी राज्यों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। अधिकांश राज्यों ने इस पर काबू पा लिया, पर कोरोना के बाद से राजस्थान में 20 प्रतिशत, झारखंड में 7.5 प्रतिशत और हरियाणा में 7 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ गई। वहीं त्रिपुरा ने रोजगार में सबसे अधिक 31 प्रतिशत की रिकवरी की है।

सीएमआइई के आंकड़ों के मुताबिक देश में मार्च 2020 में बेरोजगारी दर 6.5 फीसदी से बढ़कर फरवरी 2022 में 8.1 फीसदी पहुंच गई। मार्च 2020 से फरवरी 2022 के बीच ओडिसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने बेराजगारी पर बहुत अच्छे से काबू पाया है। कम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। *(रा.प., 25.03.22)*

बची रह गई पीएम केयर्स फंड की राशि

कोरोना काल में मोदी सरकार की ओर से स्थापित पीएम केयर्स फंड में आए 10,990 करोड़ रुपए में से सरकार आधी रकम भी खर्च नहीं कर पाई। इसमें से 3976 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। फंड की ऑडिट रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। मार्च 2020 में इस फंड की स्थापना की गई थी। इसका मकसद कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचाना था।

ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि फंड में चंदे के रूप में मिली रकम में से मात्र 36 फीसदी रकम ही खर्च की गई है। फंड में 495 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा भी आया था। फंड से अब तक 1,392 करोड़ की खरीददारी की। इनमें 6.6 करोड़ रुपए की वैक्सीन व 1,311 करोड़ रुपए के 50 हजार वेंटिलेटर शामिल हैं।

(रा.प., 09.02.22)

उज्ज्वला योजना में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा

उज्ज्वला योजना के तहत देश में 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन देने थे। लक्ष्य पाने के लिए तेल कंपनियों ने कनेक्शन फर्जी बांट दिए। सिलेंडर री-फिल नहीं हुए तो राज खुला। सीएजी ने प्रदेश के 33 लाख सहित देश के ऐसे 1.75 करोड़ गैस कनेक्शनों पर रोक लगा दी है। डीलरों को रिकवरी के लिए कहा है, मगर डीलरों ने रिकवरी से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार को 3 हजार करोड़ रुपए तक का फटका लग सकता है।

योजना के अनुसार नियमानुसार कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम से दिए जाने थे। पूरे परिवार के आधार कार्ड लेकर केवाइसी करनी थी कि पहले से परिवार के अन्य सदस्य के नाम गैस कनेक्शन न हो। लेकिन कंपनियों ने डीलर्स को कह दिया कि जिस महिला के नाम से कनेक्शन नहीं हो, उसी का आधार अटैच कर कनेक्शन दे दिए जाएं। इससे उन परिवारों ने भी कनेक्शन ले लिए जिनके पास पहले से कनेक्शन हैं। *(दै.भा., 28.02.22)*

जल जीवन मिशन में झूंठे आंकड़े

प्रदेश में जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने 60 हजार करोड़ के जल जीवन मिशन में झूंठे आंकड़ों की जमकर मिलावट की है। पोर्टल पर फर्जीवाड़ा कर 'हर घर नल कनेक्शन' तो दिखा दिया, पर हकीकत में उन ढाणियों व गांवों में टंकियों, पाइपलाइन व नल लगाने का काम ही नहीं हुआ। अब भी हर दिन सार्वजनिक नलों पर पानी के लिए कतार लगती है।

लोगों का कहना है कि इंजीनियरों ने घर-घर नल कनेक्शन का वादा कर आधार की कापी ले ली और पोर्टल पर झूंठी एंट्री कर दी। पूरे मामले पर जल जीवन मिशन के डायरेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इंजीनियरों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। *(दै.भा., 18.02.22)*

देश में 84 फीसदी की जेब पर संकट

कोरोना काल के 18 माह में देश के 100 अरबपतियों की संपत्ति 274.6 फीसदी बढ़कर 775 अरब डॉलर हो गई। पिछले एक साल में ही इसमें 352 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश के 84 फीसदी परिवारों की आय कम हुई है। इस दौरान देश में अरबपति 102 से बढ़कर 142 हो गए।

यह चौंकाने वाले तथ्य ऑक्सफैम इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट में सामने आए हैं। ऑक्सफैम इंडिया के सीइओ अमिताभ बेहर के अनुसार आर्थिक कमजोरी प्रतिदिन कम से कम 21 हजार या हर चार सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। महामारी ने लैंगिक समानता को 99 साल से 135 साल पीछे धकेल दिया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अमीरों पर संपत्ति कर लगाकर मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। *(रा.प., 17.01.22)*

अजमेर डिस्कॉम में एक और घोटाला

बिजली चोरी व छीजत में कमी लाने के नाम पर किसानों को अलग फीड़र से बिजली देने के लिए चलाए गए फीडर सेग्रीगेशन प्रोग्राम से बिजली छीजत में कमी अनुमान के मुताबिक तो नहीं आई, लेकिन इसमें जम कर घोटाला हुआ।

अजमेर डिस्कॉम ने फीडर सेपरेशन के नाम पर प्रति फीडर साढ़े 38 लाख रुपए खर्च कर डाले, जबकि जोधपुर डिस्कॉम में प्रति फीडर केवल 9.57 लाख रुपए में ही यह काम हो गया। अजमेर डिस्कॉम ने जोधपुर डिस्कॉम से चार गुना से अधिक राशि खर्च की। यदि जोधपुर की रेट अपनाई जाती तो अजमेर डिस्कॉम को करीब 51 करोड़ खर्च करने पड़ते। जबकि अजमेर डिस्कॉम ने 533 फीडरों के लिए 203 करोड़ रुपए खर्च किए। *(रा.प., 19.02.22)*

पानी बिलों की बकाया वसूली टेढ़ी खीर

प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा है। इसके चलते राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में अफसर राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश का जलदाय विभाग अन्य विभागों के मुकाबले राजस्व वसूली को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा है।

जयपुर शहर में पीएचडी इंजीनियरों को जल उपभोग के 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बकाया बिलों की वसूली करनी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया पानी के बिलों पर ब्याज व पैनल्टी को माफ करने की घोषणा की। घोषणा के बाद पीएचडी के मुख्य अभियंता व अन्य अफसर छूट के आदेश निकाल कर यह मान कर सो गए कि बकाया का भुगतान करने के लिए अब उपभोक्ताओं की लाइन लग जाएगी। *(रा.प., 25.03.22)*

अल्पसंख्यकों को नहीं बंटे ऋण

शिक्षा-रोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाने की बात हो या अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास बनवाने की, दोनों ही योजनाएं खोखली साबित होती दिख रही है।

युवाओं को शिक्षा-रोजगार के लिए जयपुर जिले में इस वित्तीय वर्ष में मात्र 42 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ है। अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी होने के बावजूद अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड यह बजट ही नहीं बांट पाया। लोन के लिए इच्छुक हजारों लोगों को नियमों की जटिलता के चलते ऋण नहीं मिल पा रहा। *(रा.प., 12.03.22)*

शहर में गंदगी यथावत, निगम का खजाना साफ

घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीवीजी ने निगम से काम लेने के बाद ठेका दूसरे वेंडर्स को सबलेट कर दिया और सालाना सवा करोड़ रुपए कमाती रही। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ऐसा कर वह अब तक 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा चुकी है। बीवीजी निगम को जो बिल पेश करती उसका 50 फीसदी भुगतान कर दिया जाता। कंपनी वेंडर्स को उसमें से 60 फीसदी भुगतान कर देती। कई वेंडर्स को तो कंपनी ने पूरे पैसे भी नहीं दिए।

ठेका सबलेट करने के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई जो कई सवाल खड़े करती है। निगम ने एक टन कचरा उठाने के 1800 रुपए लिए तो वेंडर्स को सबलेट कर 1000 रुपए प्रति टन का अनुबंध किया। कंपनी ने कचरे से कमाई का रास्ता निकाल लिया और इसी से नगर निगम का खजाना साफ होता रहा। *(रा.प., 24.01.22)*

केंद्रीय बजट 2022-23

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। भारत की स्वतंत्रता का यह 75 वां वर्ष है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के बजट में अगले 25 वर्षों के विकास का ख़ाका भी सामने रखा है। माना जा रहा है, यह देश को आत्मनिर्भर व पूरी तरह सम्पन्न बनाने की दूरगामी सोच है, जो आगे जाकर एक 'मील का पत्थर' साबित होगी:

किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

वित्तमंत्री ने बजट में खेती किसानी से जुड़े कामों के लिए 1,51,521 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। खेती की नई तकनीक से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। राज्यों के अधीन आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों में सिलेबस बदलने के लिए कहा जाएगा। इसमें कृषि से जुड़े नए कोर्स शामिल होंगे। आधुनिक खेती एवं जैविक खेती (ऑर्गेनिक फॉर्मिंग) को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट में 12,954 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, एमएसएमई के लिए ईसीएलजी योजना को 50 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मार्च 2023 तक बढ़ाना बेहतर कदम माना जा रहा है। बजट में करीब 68,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि और 15,500 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। 'किसान ड्रोन' से फसलों की पहचान, जमीन के रिकॉर्ड व कीटनाशक के छिड़काव जैसे कई काम होंगे।

आधारभूत ढांचा होगा और ज्यादा मजबूत

बजट में आधारभूत ढांचे की नींव को और मजबूत करने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सौर व पवन ऊर्जा संबंधी उपक्रमों आदि का बजटीय आवंटन 35.4 फीसदी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट में आवास और शहरी विकास के लिए 76,549 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गरीबों व जरूरतमंदों के लिए 80 लाख सस्ते आवास बनाने के लिए 48 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बजट में 19 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए आवंटित है। एक्सप्रेसवे के लिए गति शक्ति प्लान अस्तित्व में आएगा। अगले तीन सालों में रेलवे नेटवर्क बढ़ाते हुए 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने और रेलवे स्टेशनों के विकास की बात की गई है। राज्यों से बेहतर नगर नियोजन के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। हर घर नल से जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। सौर ऊर्जा और उससे जुड़े उपकरणों के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुनियादी ढांचे के विकास से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

ऑनलाइन मिलेगा सेहत का लेखा-जोखा

वित्तमंत्री ने बजट में 86,606 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया है। इस बार खास बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। मानना यह रहा है कि कोरोना महामारी से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है। स्वास्थ्य से जुड़ी कई जानकारियां ऑनलाइन मिलेंगी। इसमें हर नागरिक की यूनिक हैल्थ आइडेंटिटी होगी, अर्थात आपकी सेहत का लेखा-जोखा होगा।

देश में 75 हजार नए ग्रामीण हैल्थ सेंटर और खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। बजट में 10 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटित है। अमृत शहरों में स्वच्छता के लिए करीब 2 लाख 80 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को दी अहमियत

बजट में 1,04,278 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा मद में रखा गया है। कोविड महामारी की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। इसे देखते हुए डिजिटल शिक्षा को ज्यादा अहमियत दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 39,553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पीएम ई-विद्या योजना के तहत वन क्लास - वन टीवी चैनल को 12 की जगह 200 टीवी चैनल्स पर शुरू किया जाएगा।

कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करते हुए पूरक पढ़ाई कराई जाएगी। सभी भाषाओं में मजबूत ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा। जो इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि से संचालित हो सकेगा। घर बैठे विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा।

ग्रामीण विकास पर रखी खास नजर

गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में हाथ खोलकर 2,06,293 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। इस योजना के तहत 80 लाख आवासों का निर्माण चिन्हित हितग्राहियों के लिए होगा।

मनरेगा सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली योजनाओं पर 1,35,944 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में इस बार ई-पंचायत से गांवों को जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

अलग-अलग तरीकों से पनपेंगे रोजगार

बजट में अलग-अलग तरीकों में ढेरों नौकरियों के सृजन की घोषणा की गई है। अकेले मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख और आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। इस घोषणा से युवाओं में आत्मबल बढ़ेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (जीसीटीएमएसई) योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपए का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को अतिरिक्त कर्ज का प्रावधान है।

एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ की गारंटी लिमिट का दायरा बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का फायदा भी कोरोना की मार से डूबते उद्योगों को मिलेगा।

राजस्थान राज्य बजट 2022-23

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट रखा। बजट में खेती-किसानी को लाभदायक बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को शतप्रतिशत निःशुल्क करने, शिक्षा की नींव को मजबूती देने, बुनियादी ढांचे के विकास को अहमियत देने, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर लाभान्वित करने और महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन मुफ्त देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं कर सभी को खुश करने का प्रयास किया गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास का खाका

बजट में 25,260 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित है। पचास यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। अन्य उपभोक्ताओं को भी बिल में 175 रुपए से 750 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसमें 300 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिन्हें स्लेब के अनुसार छूट दी जाएगी। हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम पर 60,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कई बड़ी जल प्रदाय परियोजनाओं की सौगात भी बजट में है।

प्रदेश की 24 पेयजल परियोजनाओं पर 13,921 करोड़ रुपए के काम होंगे। प्रदेश के 4 हजार किलो मीटर राजमार्ग पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट में है। एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गो को पहले चरण में 2 लेन किया जाएगा। प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण तीन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व उन्नयन पर 3,133 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है

प्रगति का आधारः कृषि क्षेत्र का विकास

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र देश की प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए बजट में खेती और किसानों को कई योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को 2 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5 हजार करोड़ रुपए किया गया है।

बजट में किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अकृषि क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर एक लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में जैविक खेती को खास अहमियत देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज मुफ्त

प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व देते हुए सरकारी अस्पतालों में मिल रही निःशुल्क दवा व जांच योजना तथा चिरंजीवी बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इससे अब आमजन को सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकारी अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को शत-प्रतिशत निःशुल्क कर, सरकार दवाओं और जांच योजनाओं की सुविधाओं का विस्तार करेगी। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

प्रदेश में 15 खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,224 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान बजट में प्रस्तावित है। इससे मेडिकल शिक्षा और ज्यादा मजबूत हो सकेगी।

मजबूत होगी शिक्षा की नींव

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई का बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि के ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे। शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के प्रति रुझान को देखते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का दायरा बढ़ाया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक-एक हजार अंग्रेजी माध्यम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में अब 3200 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो जाएंगे। इन स्कूलों के लिए 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती होगी।

प्रदेश के सभी 3820 सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उच्चप्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा तथा उच्च प्राथमिक विधालयों को भी अपग्रेड कर सीधे सीनियर सैकंडरी स्कूल स्तर पर लाया जाएगा।

उद्योगों को राहतः पनपेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री द्वारा बजट में उद्योग क्षेत्र को दी गई रियायतों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और उससे लाखों रोजगार के अवसर पनपेंगे। रिफाइनरी के पास ही पेट्रोलियम सह उत्पाद आधारित पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआइआर) का खाका तैयार है। बजट में 17 जिलों में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है।

सरकार ने पहले चरण में वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र विहीन उपखंडों पर 64 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की थी। इन पर काम चल रहा है। बजट में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में होगा।

महिलाओं को मिलेगा घर बैठे लाभ

अब महिलाएं घर से ही काम कर आजीविका में योगदान दे सकेंगी इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में जॉब वर्क योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 20 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन मुफ्त देने की घोषणा भी बजट में की गई है। इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्चा आएगा।

कर्मचारी खुशः पुरानी पेंशन स्कीम लागू

बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश में 2004 के बाद लगे करीब 5 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी पिछले कई सालों से नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे। विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में एक अप्रेल, 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की बजट में घोषणा की गई है।

सरकार ने बांध दिए एसीबी के हाथ

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया, जिसे सरकार ने सरकारी दस्तावेज भी बना दिया। इसके बावजूद जांच की अनुमति नहीं मिलने से पद के दुरुपयोग के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के हाथ बंधे हुए हैं। हालात यह है कि एक साल में ब्यूरो को पद के दुरुपयोग के 273 मामलों में से करीब 15 मामलों में ही जांच शुरू करने की इजाजत मिली है।

केंद्र सरकार ने लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए अनुमति अनिवार्य करने सहित अन्य प्रावधान जोड़ने के लिए 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया। संयोग से प्रदेश में उसी साल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया गया और घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया। 273 मामलों पर इजाजत देने का प्रश्न राज्य विधान सभा में भी उठा। लेकिन सरकार की आनाकानी से एसीबी कार्रवाई नहीं कर पा रही।

(रा.प. 06.01.22, 07.01.22)

ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तो तोड़ा रिकॉर्ड

प्रदेश में जितनी तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) काम कर रही है। साल-दर-साल एसीबी की कार्रवाई में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में पिछले तीन साल के जनवरी-फरवरी महीने का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वर्ष 2022 में रेकार्डतोड़ कार्रवाई हुई है।

महानिदेशक (एसीबी) बीएल सोनी ने बताया कि इस साल ट्रैप की कार्रवाई 63 की गई है, जो कि तुलनात्मक सबसे अधिक है। इसके अलावा दो केस आय से अधिक संपत्ति के दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि इस साल एसीबी ने रेकॉर्ड 68 केस में जांच करके कोर्ट में चालान पेश किए हैं। *(रा.प., 03.03.22)*

घूसखोरी में शहरी सरकार ने ली बढ़त

प्रदेश में अब तक ग्रामीण सरकार के सरपंच, वार्डपंच और प्रधान घूसखोरी में शहरी सरकार के महापौर, चेयरमैन और पार्षदों से कहीं आगे रहे हैं। लेकिन पिछले 6 माह में शहरी सरकार के जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण सरकार के जनप्रतिनिधियों को पीछे छोड़ दिया है। इस साल शहरी सरकार के 12 चेयरमैन, पार्षद, महापौर पति, चेयरमैन पुत्र, पार्षद पति घूस लेते गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पिछले साल जबकि यह आंकड़ा शून्य था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पिछले आठ साल में की गई ट्रैप कार्रवाई की पड़ताल की तो यह तथ्य सामने आया। शहरी सरकारों की यह शर्मनाक बढ़त है। हकीकत में शहरी सरकार के जन प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।

(दै.भा., 05.02.22)

विभागों ने कहा हमें जांच नहीं करानी

राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग टॉप पर है। प्रदेश में सबसे अधिक मामलों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग दबा कर बैठा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में दूसरे नंबर पर स्वायत्त शासन विभाग है। सरकारी 36 ऐसे विभाग हैं, जो भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। जिनमे सात विभागों में तो दो वर्ष से शिकायतों की फाइल पर धूल जमी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार को लेकर आए नए कानून की 17 ए धारा ने सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार के मामलों में बेखौफ कर दिया। इस कानून के तहत एसीबी मिलने वाली शिकायतों पर सीधी जांच नहीं करेगी और शिकायत मिलने पर संबंधित विभागाध्यक्ष से जांच करने की अनुमति मांगेगी। अनुमति मिलने के बाद ही एसीबी जांच कर सकती है। इसके चलते 6 विभागों में भ्रष्टाचार के 10 मामलों की जांच करवाने से सीधा इनकार कर दिया। इनमें एक बैंक भी शामिल है। *(रा.प., 08.01.22)*

राजस्थान में बढ़ी रिश्वतखोरी

राजस्थान में 2020 के मुकाबले 2021 में 40 प्रतिशत भ्रष्टाचारी बढ़े हैं। यह जानकारी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के आंकड़ों से सामने आई है। कुल 468 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया है। सर्वाधिक भ्रष्ट कर्मचारी राजस्व, पुलिस, पंचायतीराज, ऊर्जा विभाग व स्वायत्त शासन विभाग के पकड़े गए हैं। वहीं पकड़े गए 32 लोकसेवक भारत सरकार के हैं।

एसीबी के डीजी बीएल सोनी के अनुसार साल 2021 में 501 केस दर्ज हुए। इनमें 30 ट्रेप की कार्रवाई 42 पद के दुरुपयोग व 29 आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। साल 2021 में सर्वाधिक 575 मामले कोर्ट में पेश किए गए हैं। एसीबी न्यायालयों ने 144 मामलों का निस्तारण किया, जिनमें 55 मामलों में दोषियों को सजा हुई। सरकारी विभागों से 90 प्रतिशत मामलों में अभियोजन स्वीकृति मिली। *(दै.भा. एवं रा.प., 06.01.22)*

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना आवश्यक

हाल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एक दशक में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एजेंसियों को मजबूत करने, वित्तीय अपराध पर नकेल कसने और सार्वजनिक खर्च को पारदर्शी बनाने जैसी कई सिफारिशें की गई हैं।

दूसरी ओर कुछ देशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ज्यादातर महिलाओं की नियुक्ति करने का तरीका अपनाया है। मानना है कि जहां महिला पुरुष समानता है, वहां भ्रष्टाचार का अंतर भी मिट सकता है। महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में कम अपराध करती हैं। लेकिन पिछले 50 वर्षों में महिलाएं भी अपराधी बन गई हैं। यह आंशिक बढ़ोतरी ही है। कई देशों में भ्रष्टाचार पर हुए शोधों से निष्कर्ष निकला है कि महिलाएं कम बेईमान होती हैं। उनके पास भ्रष्टाचार के मौके कम होते हैं। यदि ऐसा करती हैं तो उनके साथ सख्ती भी ज्यादा होती है। *(दै.भा., 20.02.22)*

बिजली चोरों को लग रहा करंट

जयपुर डिस्कॉम ने 12 जिलों में विजिलेंस चेकिंग बढ़ा दी है। विजिलेंस विंग व ओएंडएम विंग के इंजीनियरों ने बीते छह महीनों में 44 हजार से ज्यादा बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं और उन पर करीब 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट के मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा सुनवाई कर निस्तारण किया जा रहा है। ताकि आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन कर राहत दी जा सके।

बिजली चोरी की धरपकड़ से डिस्कॉम में छीजत का आंकड़ा कम हो रहा है। इससे ईमानदार उपभोक्ताओं को आगामी टैरिफ में राहत मिलने की उम्मीद है। डिस्कॉम प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बिजली छीजत कम करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त बिजली सप्लाई करने के लिए इंजीनियरों को हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। *(दै.भा., 28.01.22)*

50 यूनिट तक बिजली बिल होगा शून्य

राज्य में 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल खत्म करने की तैयारी है। इसमें करीब 70 लाख से अधिक उपभोक्ता शामिल होंगे, जो कुल बिजली उपभोक्ताओं के करीब आधे हैं। सरकार बिल निःशुल्क करने और बाकी उपभोक्ताओं को छूट की घोषणा एक अप्रेल से लागू करने की तैयारी में है।

विद्युत शुल्क में सब्सिडी की घोषणा सरकार बजट में ही कर चुकी है। अब इनके बिल को फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और अरबन सेस से भी मुक्त करने की कवायद चल रही है। इनमें बीपीएल, छोटे घरेलू व सामान्य उपभोक्ता शामिल होंगे, जिनका बिजली उपभोग पचास यूनिट तक है। डिस्कॉम ने इसी आधार पर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। अंतिम मुहर सरकार लगाएगी। *(रा.प., 23.03.22)*

अपनाएंगे फ्लोटिंग पैनल्स का नवाचार

सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के साथ बांधों से भाप बन कर उड़ते पानी को बचाने का आंध्रप्रदेश समेत दक्षिण के कई राज्यों में किया गया नवाचार सफल साबित हो रहा है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सिरमौर बने राजस्थान में भी इस नवाचार को प्रदेश के जल भंडारों पर अपनाने के प्रयोग संभव है।

राजस्थान में फिलहाल 22 बड़े बांध हैं। यदि इन बांधों और अन्य जल निकायों पर फ्लोटिंग पैनल्स (पानी में तैरते हुए हुए फोटो वोल्टिक सौर पैनल्स) लगाए जाते हैं, तो सौर ऊर्जा उत्पादन की ताकत को दोगुना किया जा सकता है। साथ ही बांधों के पानी के वाष्पीकरण को कम कर जल संरक्षण में भी बेहतर काम किया जा सकेगा। *(रा.प., 10.02.22)*

कंपनियों में होगा वित्तीय सुदृढ़ीकरण

विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा 90 हजार करोड़ पार करने के बाद अब इन सभी कंपनियों में वित्तीय सुदृढ़ीकरण होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी संभावित विकल्पों पर सुझाव के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ही तीनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, तकनीकी प्रतिनिधि एवं वित्त अधिकारी होंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद इस तरह की कवायद शुरू हुई है। यह कमेटी विद्युत कंपनियों को फिजूलखर्ची रोकने, खर्चा व बिजली छीजत कम करने, घाटे को कम करने के समाधान और सुझाव देगी। बैंकों व वित्तदायी संस्थाओं से महंगे ब्याजदर पर लिए गए ऋण को रिस्ट्रक्चिरिंग किया जाएगा। ऐसा हुआ तो इससे बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत मिल सकेगी। *(रा.प., 21.01.22)*

कृषि विद्युत वितरण कंपनी का होगा गठन

राज्य सरकार ने कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन की तैयारी कर ली है। कंपनी का उपनाम 'एग्रीकॉम' सुझाया गया है। इस कंपनी के जरिए सरकार का फोकस 15 लाख किसानों को सौर ऊर्जा के जरिए दिन में ही बिजली उपलब्ध कराना और सालाना 16 हजार 500 करोड़ रुपए के सब्सिड़ी बोझ को 50 से 70 फीसदी तक कम करना है।

इसके लिए केंद्र सरकार की कुसुम योजना (कंपोनेंट ए व सी) को पूरी तरह लागू करने पर ध्यान रहेगा। कुसुम योजना के जरिए सौर उत्पादन बढ़ाने पर खास फोकस होगा। इससे 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी का बोझ कम हो सकेगा। इसकी जिम्मेदारी भी इसी कंपनी को देना प्रस्तावित किया गया है।

(रा.प., 01.02.22, 10.02.22)

सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगाई ऊंची छलांग

सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान ने ऊंची छलांग लगाई है। प्रदेश 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर देश में पहले पायदान पर काबिज है। इसके बाद अब कर्नाटक और गुजरात काफी पीछे हो गए हैं। कर्नाटक 7534 मेगावाट क्षमता के साथ दूसरे और गुजरात 6309 मेगावाट क्षमता के साथ तीसरे पायदान पर है।

केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी तक जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने 10.5 गीगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली है। अब देश में कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट सोलर एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में अब राजस्थान की मुख्य हिस्सेदारी होगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 13.02.22)*

बिजली ली पर नहीं चुकाए बिजली बिल

बिजली के बकाया बिलों ने प्रदेश के तीनों डिस्कॉमों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश में 7500 करोड़ रुपए (जनवरी तक) बकाया हैं, जिसे वसूलने के लिए पूरा महकमा जुटा हुआ है। इसमें 2390 करोड़ रुपए अकेले सरकारी ऐजेंसियों में बकाया चल रहे हैं।

मुख्य सचिव से लेकर वित्त सचिव तक इन ऐजेंसियों को बकाया चुकाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। इस पूरी रकम का भार ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। बकाया राशि का सीधा असर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। *(रा.प., 16.03.22, 20.03.22)*

जल जीवन मिशनः प्रदेश में हुआ बेहतर काम

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत 3213 गांवों के लिए 6872 करोड़ रुपए की राशि की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 27 जिलों की 6.56 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 28 महीनों में कोरोना महामारी के लॉकडाउन जैसे व्यवधानों के बाद भी राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य में 10.05 लाख घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक राज्य में 1.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया गया है। मिशन के तहत 2024 तक 84 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए राज्य के साथ केंद्र सरकार भी पूरी सक्रियता दिखा रही है। *(रा.प., 07.01.22)*

नल कनेक्शन की जगह बनेंगे टांके

प्रदेश के जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर एवं अलवर जिले ऐसे है जिनमें जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन जारी करना संभव नहीं है। अब इन जिलों में मिशन के तहत 365 करोड़ की लागत से 30 हजार लीटर की क्षमता के 20 हजार टांके बनाए जाएंगे। इससे इन जिलों के डेढ लाख से ज्यादा परिवारों के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी। इन टांकों में सोलर लिफ्ट भी लगाई जाएंगी।

जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बताया कि प्रदेश के जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर एवं अलवर जिले ऐसे है जिनमें नल कनेक्शन जारी करने में कई तरह की दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को दूर करते हुए सामुदायिक टांकों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मिशन के तहत 6155 करोड़ की लागत से 18 जिलों के 2486 गांवों में 5 लाख जल कनेक्शन को मंजूरी दी गई है। *(रा.प., 26.02.22)*

भूजल खतरनाक पदार्थों से महफूज है?

प्रदेश के सभी 33 जिलों का भूजल फ्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा और लवणता से प्रभावित है। इनकी मात्रा तय मानकों से ज्यादा मिली है। अधिकांश क्षेत्र आंशिक प्रभावित है, लेकिन कुछ इलाकों में इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं है। फिर भी राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले के भूजल में कैडियम और क्रोमियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा नहीं पाई गई।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के केवल तीन जिलों के कुछ इलाकों में ही लेड की मात्रा अनुमत्य सीमा से कुछ ज्यादा मिली है। राजस्थान का भूमिगत जल अभी भी कई राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। कुछ सालों से प्रदेश के भूजल में खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा घटी है। *(रा.प., 10.03.22)*

लाइनें नई डाल दीं तो पानी गंदा क्यों?

जयपुर शहर के चारदीवारी, सोडाला, हसनपुरा, आदर्श नगर, जवाहर नगर सहित अन्य कई इलाकों में गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें आते ही जलदाय विभाग के इंजीनियर पाइप लाइन बदलने के प्रस्ताव बना लेते हैं। ताकि टेंडर कर ठेकेदार को काम दे सकें। चारदीवारी में दूषित पानी से राहत व पेयजल सप्लाई में सुधार के लिए पिछले पांच सालों में 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद नतीजा सिफर है।

पाइप लाइनें 'बदलती' जा रही है...गंदा पानी आता जा रहा है। पाइप लाइनों का न नक्शा तय है और न रूट। ऐसे में ये लाइनें कई जगह जर्जर पुरानी लाइन सीवरेज चैंबर से होकर गुजर रही है। इससे सीवरेज का पानी इन लाइनों में घुलकर आपूर्ति के दौरान घरों में पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े गड़बड़झालों का खुलासा होने पर भी न तो जांच होती है और न ही सैंपलिंग और ऑडिट?

(दै.भा., 08.01.22)

पानी की किल्लत पर जताई चिंता

राजस्थान विधानसभा में लगभग हर विधायक ने पेयजल किल्लत को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि जल जीवन मिशन में नल तो घर-घर लगाए जा रहे हैं, लेकिन पानी के नए स्रोत तलाशने को लेकर कुछ काम नहीं हो रहा। इन नलों में पानी कहां से आएगा।

प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं। प्राकृतिक पेजजल स्रोत तालाब, कुएं, बावड़ी और एनीकटों को संवारने की जरूरत है। गांवों में जल जीवन योजना के तहत लग रहे नलकूपों को लेकर कहा कि ग्राम पंचायतों के पास पैसा नहीं है। इनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जेईएन और लाइनमैन के पद खाली चल रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। *(रा.प., 09.03.22)*

प्रदेश में चल रहा है जल संरक्षण का काम

वन विभाग की ओर से जंगलों को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करने के साथ ही अब जल संचय पर भी फोकस किया जा रहा है। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर डिविजन में ट्रेंच खोद कर जल संरक्षण किया जा रहा है। इससे जल स्तर में वृद्धि के साथ जमीन में नमी की मात्रा भी सुधर रही है। इससे पौधों के जल्दी से बढ़ने की उम्मीद है।

विभाग के अनुसार 50 हेक्टेयर की साइट से वर्षा ऋतु में 4 बार पानी भरने से 1 करोड़ 62 लाख लीटर पानी स्टोर होता है। विभाग की ओर से प्रदेश में 10,675 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रेंच खोदी जा रही है। इसमें प्रदेश में 50 हेक्टेयर की 213 जगह साइट बनाई जाएगी। प्रदेश में सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में 3075 हेक्टेयर एरिया में स्ट्रेंच खोदी जा रही है। *(दै.भा., 28.02.22)*

कागजों में कैनालः प्यासा आधा राजस्थान

इंद्रा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) ने पश्चिमी राजस्थान को समृद्ध किया पर पूर्वी राजस्थान आज भी प्यासा है। यहां की स्थिति सुधारने के लिए 2016 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट(ईआरसीपी) का विचार आया, लेकिन तभी से यह प्रोजेक्ट केंद्र-राज्य सरकार के बीच पत्राचार में उलझा है।

इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य बजट में 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोजेक्ट में देरी से पूर्वी राजस्थान का जमीनी सच जानने के लिए भास्कर के दो रिपोर्टर्स ने 13 जिलों के लोगों के साथ 15 दिन बिताए, सामने आया कि पानी की समस्या वहां पलायन और रोगों का कारण बन रही है। *(दै.भा., 22.03.22)*

घूंघट में भी जागरूक हो रही महिलाएं

तकनीक के बल पर घूंघट व घर की दहलीज में रहकर भी प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो रही हैं। उत्पीड़न, छेड़छाड़ व घरेलू हिंसा के मामले में सीधे देश के राष्ट्रीय महिला आयोग तक दस्तक दी जा रही है। हेल्पलाइन के अलावा ई-मेल के जरिए घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवाने का ग्राफ बढ़ा है। पिछले एक वर्ष में राज्य से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक शिकायतें कोरोनाकाल के दौरान की हैं।

अब महिलाएं पुलिस थानों तक नहीं जाती हैं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाती हैं, जिन पर आयोग तुरंत एक्शन लेता है। जरूरी होने पर संबंधित एसपी को तत्काल अवगत कराते हैं। केवल दुष्कर्म ही नहीं जमीन जायदाद व उत्पीड़न की शिकायतें भी महिला आयोग को मिल रही हैं।आयोग में मामले अब तत्काल निपटाए जा रहे हैं। *(रा.प., 11.03.22)*

बेटियों के लिए खुले उच्च शिक्षा के द्वार

प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेटियों के नामांकन की सुखद तस्वीर सामने आई है। 15 साल पहले जहां प्रति 100 लड़कों पर मात्र 63 लड़कियां ग्रेजुएशन-पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थीं, अब यह आगे निकलकर 107 हो गई हैं। इस साल प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों को मिला कर 13,02,485 नामांकन हुए हैं। इनमें यूजी-पीजी में मिलाकर 6,29,091 छात्र हैं, जबकि छात्राएं 6,73,394 हैं।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में छात्राओं के लिए राजकीय निधि कोष की राशि माफ करने, पीजी में सीट खाली रहने पर छात्राओं को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट देने, नए सरकारी कॉलेज खोलने, निःशुल्क पुस्तकें देने जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। इससे छात्राओं का नामांकन बढ़ा है। *(दै.भा., 16.02.22)*

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं की हकीकत

लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर राजस्थान समेत अधिकांश राज्य गंभीर नहीं है। हालात यह है कि किसी भी प्रदेश ने केंद्र से मिला पूरा पैसा उपयोग में नहीं लिया। राजस्थान में छह वर्ष में योजना राशि में से 60 फीसदी से ज्यादा पैसा लैप्स कर दिया।

हाल ही विधान सभा में भी यह मामला उठा। हर साल बजट लैप्स हो रहा है, ऐसे में लिंगानुपात एक हजार तक कब पहुंचेगा। जिलों में सालाना करीब एक करोड़ रुपए का बजट होता है, जिसे दूसरे मदों में खर्च करने की शिकायतें आती है। *(रा.प., 03.03.22)*

कॉरपोरेट क्षेत्र में बढ़ी महिला भागीदारी

भारत सहित दुनियाभर के कॉरपोरेट जगत में शीर्ष पदों पर महिलाएं दमदार मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। डेलॉइट की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कंपनियों में महिला सीईओ की संख्या बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई है, जो 2018 में 3.4 प्रतिशत थीं।

कंपनियों के निदेशक मंडल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 17.1 प्रतिशत हो गई है, जो वर्ष 2014 में सिर्फ 9.4 फीसदी थीं। हालांकि वर्ष 2021 में नेतृत्व के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है परन्तु निदेशक मंडल में चेयरमैन के रूप में महिलाओं की भागीदार मात्र 3.6 फीसदी है। फिर भी, देखा जाए तो 67 फीसदी लोगों ने माना है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं बेहतर वित्तीय फैसले लेती हैं। देश की जीडीपी में अभी 18 प्रतिशत योगदान महिलाओं का है। *(रा.प., 10.02.22)*

कृषि व्यवसाय में आगे आईं महिलाएं

प्रदेश में अब कृषि आधारित व्यवसायों में महिलाएं आगे आ रही हैं। तकनीकी मदद से आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं न केवल ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं बल्कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नवाचार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नीति आयोग के सहयोग से पिछले साल प्रदेश की 150 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप को लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।

यह काफी सुखद संकेत है। महिलाओं को समय-समय पर खेती, पशुपालन, डेयरी और कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में 20 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है। *(रा.प., 17.01.22)*

खेजड़ली गांव में बनेगा अब स्मारक

वर्ष 1730 का वह स्थान, जहां से चिपको आंदोलन की उत्पत्ति हुइ थी। जहां खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के साथ उनकी बेटियां और अन्य ग्रामीण पेड़ों से चिपक गए थे। तब मारवाड़ के महाराजा के सैनिकों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया था। यह स्थान और उनके बलिदान की कहानी तो आज भी जीवंत है। लेकिन अमृता देवी के साथ अपनी जान देने वाले उन 363 शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों से गायब है।

वहां पर करीब 292 साल के बाद स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक में उन सभी शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों को पता चल सके कि पेड़ों की खातिर अपना शीश कटाने वाले वे कौन-कौन थे? स्मारक में अमृता देवी विश्नोई की मूर्ति लगाई जाएगी। *(दै.भा., 03.01.22)*

गृहणियों के काम को कम न आंके

यह रूढ़िवादी सोच है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वे काम नहीं करती। इसे बदलना चाहिए। महिलाएं घरों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। उनके काम का कोई आर्थिक मोल नहीं माना जाता। यह धारणा खत्म होनी चाहिए। गृहणी बिना वेतन घर का काम करती है, जिसका परिवार के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों के लिए 76 प्रतिशत समय देती हैं, जो पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक है। भारत में करीब 20 करोड़ महिलाएं हर माह अवैतनिक कार्य करते हुए औसतन 40 हजार करोड़ रुपए परिवार पर कुर्बान कर देती हैं। *(रा.प., 17.01.22)*

'कट्स' इंटरनेशनल का राज्य स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी में चयन

हाल ही राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी में 'कट्स' इंटरनेशनल को एक वर्ष के लिए सदस्य नामित किया है। इस कमेटी में 'कट्स' का प्रतिनिधित्व जॉर्ज चेरियन करेंगे। 'कट्स' पिछले कई दशकों से सड़क सुरक्षा के लिए कार्यरत है और भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत गठित कई कमेटियों में शामिल है।

जॉर्ज चेरियन ने बताया कि 'कट्स' सड़क सुरक्षा के तहत नीतिगत मुद्दों, अनुसंधान एवं पैरवी के लिए लगातार सक्रिय रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी को 'कट्स' भरपूर सहयोग एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करेगा। यह कमेटी सड़क सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगी। ।

घायलों को प्राथमिक इलाज देगी पुलिस

साल 2021 में राजस्थान में 18,854 सड़क हादसों में 19 हजार से अधिक लोग घायल हुए, जबकि 10,043 की मौत हुई। प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में तत्काल इलाज न मिलने पर हजारों लोग जान गंवा देते हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस नई पहल करने जा रही है। अब पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने के बाद उनके वाहन में डिजिटल बीपी टेस्ट मशीन, हॉट वाटरबैग, पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्स, ग्लूकोजमीटर व फोल्डेबल स्ट्रेचर होगा।

हादसे वाली जगह सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, ऐसे में हजारों जानें बचाई जा सकेंगी। प्रदेश में 850 पुलिस थानों को उपकरण खरीद के लिए 85 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। जल्द ही खरीद की कार्यवाही पूरी होगी। *(दै.भा., 10.01.22)*

बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस होगा जरूरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दुपहिया वाहन पर चार साल तक के बच्चों को बैठाने के लिए हार्नेस(सेफ्टी बेल्ट) को अनिवार्य कर दिया है। अधिसूचना पर राज्य में काम भी शुरू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने फील्ड स्टॉफ को निर्देशित कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार यह नियम पूरे देश में 15 फरवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि इस तारीख के बाद हर दुपहिया चालक को छोटे बच्चों के साथ बेल्ट और हेलमेट पहनना होगा। सरकार के इस निर्णय का असर प्रदेश के 15 करोड़ वाहनों के चालकों पर पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक दुपहिया वाहन पंजीकृत है। अभी तक सामान्यतः लोग छोटे बच्चों को दुपहिया वाहन पर आगे बैठाकर ले जाते हैं। *(रा.प., 20.03.22)*

ट्रैफिक नियमों की भ्रांतियां दूर करें

भारत में हर चार मिनट में सड़क दुर्घटना के जरिए एक मौत होती है। ऐसे में यदि ट्रैफिक नियमों की पालना की जाए और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तो इन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोग ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूक रहें, दूसरों का भी ध्यान रखें। क्योंकि, छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है।

- लोकल क्वालिटी का हेलमेट पहननाः दोपहिया वाहनों में दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी होता है, लोग चालान से बचने के लिए सस्ता व हल्की क्वालिटी का हेलमेट काम में लेते हैं। नियमः 129 सीएमवी/194 डी के अनुसार आइएसआइ मार्का हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः1000 हजार रुपए।
- हाइवे पर गलत साइड ड्राइविंगः कई बार वन-वे पर लोग गाड़ी को रिवर्स में चलाते हैं या हाइवे व रिंग रोड पर विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने लग जाते हैं। नियमः 184 (ई) के अनुसार यातायात के प्राधिकरत प्रवाह के विरूद्ध गाड़ी चालन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः 1000 रुपए।
- तेज आवाज वाले हॉर्न बजानाः अटेंशन पाने के लिए लोग तेज आवाज वाले हॉर्न गाडियों में लगा लेते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। नियमः धारा 194 एफ(ए) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसे हॉर्न पर जुमार्ना देय है। अनावश्यक रूप से बजाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः 1000 रुपए।
- गाड़ी को पार्क कर, राह में बाधा बननाः प्रतिबंधित क्षेत्र के अलावा भी ऐसी कई जगह है जहां लोग गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर देते हैं। नियमः धारा 122/127/177 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी पार्क करना, गलत तरीके या गलत जगह गाड़ी पार्क करने पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः 100 से 200 रुपए।

- नाबालिक के वाहन चलाने को सही माननाः अक्सर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वाहन/स्कूटी चलाकर स्कूल जाते हैं। जबकि ये ऑटोमेटिक गेयर वाले वाहन होते हैं और इन्हें लाइसेंस के बिना चलाना अपराध है। नियमः धारा 199 ए के तहत किशोर द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पैरेंटस पर जुर्माने और तीन साल की सजा का प्रावधान है। जुर्मानाः 25 हजार रुपए।
- एलपीजी किट की सूचना न देनाः लोग अपनी गाड़ियों में एलपीजी किट लगवा लेते हैं और आर सी में अपडेट नहीं कराते, ऐसे में यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। नियमः धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः 5000 रुपए प्रति परिवर्तन।
- बेझिझक वाहन को मोडिफाइ करवानाः लोग अपने वाहन चाहे कार हो या बाइक इसमें कई तरह के बदलाव कर लेते हैं। यहां तक कि उनकी लम्बाई और ऊंचाई में भी बदलाव कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन में बदलाव नहीं करवाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नियमः धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्मानाः 5000 रुपए प्रति परिवर्तन।
- बीमा पॉलिसी के बिना ड्राइविंगः सभी मोटर वाहनों के पास हर समय वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना जरूरी है। लोग बीमा पॉलिसी या रीन्यू करवाए बिना यात्रा करते हैं। नियमः धारा 146/196 के तहत बीमा पॉलिसी का होना जरूरी है नहीं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। जुर्मानाः 2000 रुपए।

(रा.प., 09.02.22, 10.02.22)

उपभोक्ता फैसले

यात्री के कीमती सामान चोरी होने पर रेलवे जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (प्रथम) में वैशाली नगर निवासी डॉ. निशा वशिष्ठ ने परिवाद दायर कर कहा कि उसने 18 अक्टूबर 2012 को भोपाल से जयपुर के लिए तृतीय श्रेणी एसी कोच में टिकट बुक कराया था। यात्रा के दौरान रात को उसका हैंड बैग चोरी हो गया। उन्होंने जीआरपी थाना, जयपुर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसको अजमेर जीआरपी थाना में भेज दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोच अटेंडेंट और उसके साथी को गिरफ्तार कर कुछ चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया। करीबन 55 हजार रुपए की ज्वैलरी बरामद नहीं हुई। डॉ. निशा ने इसे रेलवे का सेवा दोष बताया और कहा कि सामान चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार है।

मामले की सुनवाई पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि परिवादी डॉ. निशा ने सामान रेलवे को नहीं सौंपा था, उन्हें अपने कीमती सामान की खुद सुरक्षा करनी चाहिए थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि रिजर्वेशन के बाद सफर के दौरान रेलवे यात्री का कीमती सामान चोरी होने पर रेलवे जिम्मेदार है। आयोग ने रेलवे को चोरी हुए सामान के 55 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए। साथ ही आयोग ने मानसिक संताप के 30 हजार रुपए और 10 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर भी अलग से देने के निर्देश दिए।

(रा.प., 10.01.22)

गैस पाइप में आग लगने पर एजेंसी जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता आयोग (प्रथम) में जयपुर जिले के चौमूं निवासी लादूराम ने परिवाद दायर कर कहा कि 31 अगस्त 2012 को गैस सिलेंडर का पाइप कटने से उनकी रसोई में आग लग गई। जिससे एक लाख रुपए का सामान जल गया। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2011 को अग्रवाल गैस सर्विस, चौमूं से गैस कनेक्शन लिया था, जिसके साथ चूल्हा, गैस पाइप व रेगूलेटर दिया था। ऐसे में गैस पाइप की गुणवत्ता खराब होने से आग लगने की दुर्घटना हुई। उन्होंने आयोग से गुहार की कि उन्हें गैस एजेंसी संचालक से हर्जा-खर्चा दिलवाया जाए।

मामले की सुनवाई पर गैस एजेंसी संचालक ने कहा कि पाइप की गुणवत्ता के लिए पाइप निर्माता जिम्मेदार है तथा नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार है। आयोग ने गैस एजेंसी की ओर से दी गई दलीलों को सही नहीं माना और फैसले में कहा कि कोई भी डीलर बिना चूल्हा एवं गैस पाइप के सामान्यतः गैस कनेक्शन नहीं देता। गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लगी है और उससे परिवादी का नुकसान हुआ है। आयोग ने इस सेवा दोष के लिए गैस एजेंसी संचालक को जिम्मेदार माना। आयोग ने अग्रवाल गैस सर्विस, चौमूं के संचालक को आदेश दिया कि वह परिवादी लादूराम को नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 हजार रुपए भुगतान करें और साथ ही मानसिक एवं परिवाद व्यय के तौर पर 11 हजार रुपए अलग से चुकाएं।

(रा.प., 18.01.22)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षित वित्तीय सेवाएं आवश्यक

''प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाएं बढ़ी हैं। उपभोक्ता इसका उपयोग भी करने लगा है। इसका बहुत अधिक उपयोग उपभोक्ताओं ने नोटबंदी एवं कोरोना महामारी के दौरान किया है। लेकिन डिजिटल वित्तीय सेवाओं से बहुत अधिक मात्रा में किसी न किसी रूप में धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के साथ निष्पक्ष डिजिटल सेवाएं होना आवश्यक है। सभी नियामकों को चाहिए कि इस तरह की प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि आम व्यक्ति इसका लाभ बहुत आसान तरीके से प्राप्त कर सकें।''

उक्त विचार 'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित 'सुरक्षित डिजिटल वित्तीय सेवाएं' विषयक परिचर्चा में प्रदीप महता, महामंत्री 'कट्स' ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं में निजी डाटा खोने का डर रहता है तथा कई बार उपभोक्ता साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं।

परिचर्चा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व रीजनल डाइरेक्टर मुनीष पी. कोठारी ने कहा कि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को लाभ तो मिला है लेकिन इसका सरलीकरण नहीं हो पाया है। कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं से अनभिज्ञ होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं और वित्तीय सलाहकारों को उपभोक्ताओं में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने का काम करना होगा।

कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर मनोज मीणा, इंडिक एसोसिएट के अभिषेक कुमार, भरतीय रिजर्व बैंक जयपुर के एफ.आई.डी.डी.विभाग के राकेश चन्द्र शर्मा सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने सभी संभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)